



केरल पहुंच मॉन्सून,
झारखंड में 15 के बाद
आने की संभावना

नवी दिल्ली (आजाद सिपाही)।
मॉन्सून एक हप्ते की तेरीके से
केरल पहुंच गया है। राज्य के 95
फीसदी इलाके में बारिश हो रही है। भारत मौसम विभाग (आईएमडी) ने मॉन्सून के केरल
आगमन की घोषणा कर दी है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के
अनुसार झारखंड में मॉन्सून के देखते हुए झारखंड में मॉन्सून का अनुमान है।
विधाय, उत्तर ओडिशा, छत्तीसगढ़,
मध्यप्रदेश का दृष्टिकोण इलाकों में 15
जून तक मॉन्सून पहुंच जावेगा।

सेना जमीन घोटाला : इडी की जांच तेज, कस रहा शिकंजा

अमित और दिलीप गये जेल रिमांड पर आज होगी सुनवाई

- इडी ने दोनों को कोर्ट में किया पेश, 10 दिन की मांगी रिटार्ड



आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। सेना जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (इडी) की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही, नये-नये खुलासे हो रहे हैं। इस जमीन घोटाला में करोड़ीरा अमित अग्रवाल और जगतवंशी टी-इस्टेट के मालिक दिलीप घोप की भूमिका भी समाप्त आयी है।

अप्रैल को छापेमारी की गयी थी। उसके बाद सात लोगों को प्रिपार्टर किया गया था। इनमें बड़गाहै अंचल के राजस्व उपनियोगी भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन का विक्रेता प्रदीप बागवी सहित कुल सात आरोपितों को जेल भेज दिया गया। इसके

टीएमसी सांसद अधिकारी की पली रुजिरा से चार घंटे पूछताछ की

कोलकाता (आजाद सिपाही)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भ्रातीजी और सांसद अधिकारी बनर्जी की पली रुजिरा बनर्जी से इडी ने गुरुवार को करीब बाहर घेरे पूछताछ की। कोयला घोटाले मामले में इडी ने उनको तलब किया था। दिल्ली से आयी विशेष टीम महानायक को उन्नीस पूछताछ की। गैरतलब है कि रुजिरा को उनके दो बच्चों के साथ सोमवार को कोलकाता एयरपोर्ट पर विदेश जाने से रोक गया था। इसके बाद उह्ये 8 जून को इडी के समक्ष पेंश होने को कहा गया था। समक्ष के मुताबिक वे गुरुवार दोपहर कीबी 10.30 बजे सीनीजों को लेकर एस्ट्रिट इडी के दफ्तर पहुंचे। तीन अधिकारियों ने उनसे करीब 4.30 बजे शाम तक पूछताछ की। इस पूरे मामले पर अधिक बनर्जी वे आयोग लगाया उनके प्रवार अभियान को रोके के लिए उनके परिवार को प्रताङ्कित किया जारी रहा है।

नियोजन नीति का विरोध, छात्रों ने 10 और 11 को झारखंड बंद बुलाया

- छात्रों ने ट्रैट कर चलाया अभियान

आजाद सिपाही संवाददाता

रांची। स्थानीय नीति के विरोध में झारखंड स्टेट यूनियन ने एक बार फिर झारखंड बंद का आदान किया है। 10 और 11 जून को झारखंड बंद रहेंगा। झारखंड स्टेट स्टडेंट यूनियन ने एक बार फिर सद्क के अंदर कर विरोध करने की नीति को लेकर अंदोलन के क्रम में संगठन ने सांसदों और विधायिकों का रुख किया और उससे पूछा कि नियोजन नीति के अनुसार 60 प्रतिशत सीटों पर नियुक्तियां झारखंड के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की होंगी, वहीं 40 प्रतिशत सीटें 'ओपन टू अल' हैं। छात्र इसी का विरोध कर रहे हैं कि 40 प्रतिशत सीटों पर किसी भी राज्य के बुवा झारखंड में रोजगार पा सकते हैं। इनमें झारखंड तुलुगुनाल मार्च, पंचायराना फाटटर, आदिवासी छात्र संघ, आमया और अदिवासी मूलसंस्कृत संगठन भी शामिल है। नियोजन नीति के अनुसार 60 प्रतिशत सीटों पर नियुक्तियां झारखंड के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की होंगी, वहीं 40 प्रतिशत सीटें 'ओपन टू अल' हैं। छात्र इसी का विरोध कर रहे हैं कि 40 प्रतिशत सीटों पर किसी भी राज्य के बुवा झारखंड में रोजगार पा सकते हैं। क्या चाहते हैं छात्र: बिहार पुरुगंठन अधिनियम 2000 की उत्थापन 85 के तहत झारखंड सरकार को भी यह अधिकार है कि वह संयुक्त बिहार के समय का कोई भी अध्यादेश, गजट के सकल्प की अंगीकृत कर सकती है। इसी अधिकार के तहत बिहार की 3 मार्च 1982 वाली नियोजन नीति की विरोध कर प्रवार बना है। अदानत के आदेश पर सरकार इसके माध्यम से नियुक्ति की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ छात्रों के बीच 60-40

दिल्ली में विवि कैप्स के उद्धारन मौके

पर एलजी और सीएम आमने-सामने

■ सीएम के जरीवाल के भाषण के दौरान लगे 'मोदी-मोदी' के नारे

■ एलजी सक्सेना के भाषण के दौरान 'केजरीवाल-केजरीवाल' का नारा लगा

विधानसभा समितियों के विशेषाधिकारों का संरक्षण जरूरी

■ विधायिका और कार्यपालिका में मनमुटाव से झारखंड का होगा नुकसान

■ सभापतियों की शिकायतों पर तत्काल ध्यान देना बेहद आवश्यक

■ अधिकारियों को ध्यान रखना होगा कि विधानसभा राज्य की सर्वोच्च पंचायत है

■ विधायक भी गरिमा बनाये रखने के प्रति सजग रहें, तभी राज्य आगे बढ़ेगा

झारखंड में पिछले 22 साल के दरम्यान ऐसे कई अवसर आये, जब झारखंड के नेताओं और अधिकारियों के बीच आपसी समन्वय की कमी दिखी। इसे पाटने के भी प्रयास हुए। लगा, कार्यपालिका और विधायिका के बीच यह दूरी पट जायेगी। लेकिन अभी हाल ही में राज्य विधानसभा में सदन की विभिन्न समितियों के सभापतियों और सदस्यों की बैठक में कहा गया कि राज्य के अधिकारी विधानसभा की समितियों को तबज्जो नहीं देते, तो इसकी गंभीरता एक बार फिर उजागर हुई। विकास की डगर पर आगे बढ़ रहे झारखंड में यह बात कल्पना से भी परे है कि राज्य

की सबसे बड़ी पंचायत, यानी विधानसभा की समितियों को राज्य के अधिकारी महत्व नहीं देते और उसके बुलावे पर उपस्थित होने की जहमत तक नहीं उठाते। सभापतियों की विधानसभा अध्यक्ष से यह शिकायत सचमुच गंभीर है। अपने स्थापना काल से ही इस राज्य में कई राजनीतिक प्रयोग हुए हैं। हालांकि पांचवीं विधानसभा के

आजाद सिप

लिए हुए चुनाव के बाद झारखंड इस परिपाटी को खत्म करने की दिशा में एक ठोस कदम बढ़ा चुका है। राज्य में पहली बार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में

विरोष |

ने पिछले 23 साल में कई झाँझावात देखे हैं और झोले हैं। अब इन झाँझावातों से आगे निकलने का समय है, ताकि इस राज्य की सवा तीन करोड़ आबादी की विकास की आकंक्षा को नया क्षितिज मिल सके। इस आबादी की नुमाइंदगी करनेवाली विधानसभा की समितियों के विशेषाधिकारों का संरक्षण जरूरी है। दूसरी तरफ इन समितियों में शामिल विधायकों को भी इसकी महत्ता समझानी होगी और तब वे अपने अधिकारों का सटुपयोग कर सकेंगे। इस गंभीर मुद्दे का विश्लेषण कर रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह।



राकेश सिंह

देश की आजादी के बाद जब डॉ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को देश का संविधान तैयार करने की जिम्मेवारी मिली, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती एक ऐसा विधान स्थापित करने की थी, जो देश को एकजुट रख कर उसे आगे का रास्ता बता सके और इस क्रम में देश-समाज को एकजुट भी रखे। दो साल 11 महीने और 17 दिन तक गहन शोध और अध्ययन के बाद जब उन्होंने 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और पांच परिशिष्ट वाला संविधान देश के सामने रखा, तो उसकी मौलिकता से पूरी दुनिया प्रभावित हुई। इस संविधान में एक ऐसे भारतीय संघ की परिकल्पना की गयी है, जो

तना का ना हो बाद पवानका और कार्यपालिका में तलवारें खिंची रहेंगी या खिंचने की आशंका रहेगी, तो फिर सरकार की सारी ऊर्जा उस स्थिति को सामान्य बनाने में ही खर्च हो जायेगी और लोक कल्याण की जिस अवधारणा को लेकर उसे सत्ता हासिल हुई है, वही प्राजित हो जायेगा। इसलिए विधानसभा समितियों के विशेषाधिकारों का संरक्षण जरूरी है। ये समितियां सरकार को उसके कामकाज का आहना दिखाती हैं, इसलिए कार्यपालिका को इनका समुचित सम्मान करना ही चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने समितियों के लिए नोडल अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करने की जो पहल की बाइ-एकान नहीं होता। शारखंड पर आगे ले जाने के लिए जितनी जरूरत एक प्रभावी विधायिका की है, उससे कम कार्यपालिका भी नहीं है। इसलिए दो दशक बाद झारखंड में जिसे नये राजनीतिक युग का सूत्रपात हुआ है, उसमें पहले की स्थिति को बिसरा कर नये रस्ते पर चलने की जमीन तैयार करनी होगी। इसमें समाज के सभी वर्गों का सहयोग जरूरी और अनिवार्य है। यह बात झारखंड के विधायक, अधिकारी और दूसरे लोग जितनी जल्दी समझ लेंगे, उतना ही अच्छा होगा। ऐसा करने से ही झारखंड में विकास का असली सूरज उदय होगा और इसके प्रकाश से राज्य के विकास का पथ आलोकित होगा।

रिमांड याचिका में इडी ने अमित अग्रवाल दिलीप घोष पर लगाये कई गंभीर आरोप



घोष ने ही खरीदा था।

रांची। प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने सेना जमीन घोटाले के विविध रूपों में स्थानीय उपरोक्त

सिलसिले में गिरफ्तार कारोबारी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को रिमांड पर लेने के लिए जो

याचिका अदालत में दी, उसमें कई गंभीर आरोप लगाये गये हैं। इसमें कहा गया है कि अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के बीच रिश्ता इसी बात से प्रमाणित होता है कि जगतबंधु टी इस्टेट ने अमित अग्रवाल की कंपनी को करोड़ों रुपये ट्रांसफर किये। बता दें कि सेना के कब्जे वाली जमीन को जगतबंधु टी इस्टेट के लिए दिलीप

अक्टूबर 2020 से लेकर 25 जुलाई 2022 तक इस खाते से करोड़ों रुपये का लेन-देन हुआ है। दोनों अमित अग्रवाल की कंपनी के ही कर्मचारी हैं।

यहां गोर करनेवाली बात यह है कि जगतबंधु टी इस्टेट के नाम से खुले खाते में जमा किये गये चार करोड़ 69 लाख 80 हजार रुपये में से चार करोड़ 13 लाख 87 हजार रुपये राजेश ऑटो मर्चेंटाइज प्राइवेट लिमिटेड के खाते में ट्रांसफर कर दिये गये। राजेश ऑटो मर्चेंटाइज प्राइवेट लिमिटेड अमित अग्रवाल की कंपनी है। पैसों का लेन-देन विकास जाना और दिलीप शाह नाम के व्यक्तियों ने किया है। ये

लाला गांगा दाता करोड़ रुपये में दिखाया गया

इडी की याचिका के अनुसार, जगतबंधु टी इस्टेट के मालिक दिलीप धोप ने एमएस प्लाट-557 के रूप में दर्ज चार एकड़ 55 डिसमिल भूमि की रजिस्ट्री के लिए स्टांप द्यूटी के रूप में कुल 83 लाख तीन हजार 368 रुपये खर्च किये। इस रजिस्ट्री के लिए फीस के रूप में 62 लाख 34 हजार

60 रुपये सरकार को दिये गये। नींनी कुल करीब एक करोड़ 45 लाख रुपये रजिस्ट्री के लिए स्टांप और फीस के रूप में भुगतान किये गये। जगतवंधु टी इस्टेट ने यह कम इसलिए चुकायी, क्योंकि पूरे खंड (4.55 एकड़) का सौदा त त करोड़ करोड़ रुपये में खाया गया। प्रदीप बागची ने जिस्ट्री के वर्क निवंधन दिधिकारी के सामने यह स्वीकार दी किया कि उसे सात करोड़ रुपये माइडीएफसी फर्स्ट बैंक के उक्त बाते के 11 चेक के माध्यम से ले ले हैं। इनमें सात चेक 50-50 लाख रुपये के, दो चेक एक-एक करोड़ के, एक चेक 1.25 करोड़ ला और एक चेक 25 लाख का ॥

बकौल इटी, रजिस्ट्री डाट में
लिल्लिखित यह पूरा विवरण फर्जी
।, क्योंकि इन 11 चेक में केवल
5 लाख रुपये के चेक को ही
नाया गया। बाकी 10 चेक कभी
कश ही नहीं हुए। 25 लाख रुपये
5 चेक का नंबर 461153 है।
बकि अन्य चेकों का नंबर
000003 से लेकर 000012 तक
। इसके अलावा टीडीएस की
शि का भुगतान पंजाब नेशनल
कंक की दिल्ली शाखा के खाते से
क्या गया।

चक्रधरपुर में शिक्षा के नाम पर धर्म परिवर्तन का खेल बच्चों में बांटी जा रही थी धर्म परिवर्तनवाली किताबें, गिरफ्तार



थाना को भी सूचित किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ युवक-
कर्मी अपने घरों से आए हैं जो कि वे के बीच कॉपी, पेन, पेंसिल का वितरण भी किया गया था। उप-
लब्धि के द्वारा इनमें से कई दिन

युवती गांव में आकर बच्चों का दूसरे धर्म की किताबें पढ़ा कर धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं। चक्रधरपुर थाना के एसआइ विवेक पाल दल बल के साथ गांव पहुंचे और युवकों को हिरासत में लिया। बच्चों में बांटी जा रही थी किताबें : देवगांव नीचे टोला सहित आसपास के कई इलाकों में पिछले तीन दिनों से कई लोग बच्चों को शिक्षा देने के नाम से धर्म का प्रचार कर रहे थे। बच्चों मुखिया संगीता सवाया ने कहा कि मुझे ग्रामीणों ने इसकी जानकारी दी। बताया कि कुछ युवक युवतियों ने बच्चों में चित्रांकन में रास्ता आदर्श नामक पुस्तक वितरण किया। उसमें धर्म परिवर्तन के संबंध में कई बिंदुओं पर चर्चा है। इन चित्रों पर बच्चों द्वारा रंग भराया जा रहा है। चक्रधरपुर थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार ने कहा कि देवगांव में कुछ लोगों को पकड़ा गया है। हम पूछताछ कर रहे हैं।

संपादकीय

पहलवान और सरकार में सहमति के आसार

लं वे इंतजार के बाद आखिर सरकार की ओर से पहल हुई और पहलवानों के साथ नये सिरे से बातचीत शुरू हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दखल देने के बाद बुधवार को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के आमंत्रण पर पहलवान बजरंग पुनिया और साथी मिलिक उनके निवास पर गये। वहाँ दोनों पक्षों में करीब छह घंटे लंबी बैठक हुई। इसके बाद अनुराग ठाकुर ने मीडिया को बताया कि खिलाड़ियों के साथ सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई और 15 जून तक जांच पूरी कर चार्जरीसी फाइल कर दी जायेगी। उनसे पहले बजरंग पुनिया ने सिर्फ इन्हाँ बताया था कि वे अपस में, किसान बातचीत कर आंग का कार्यक्रम बतायें, लेकिन यह साफ है कि उनके सामने सरकार की ओर से कुछ ऐसी बातें रखी गयी हैं, जिन पर उन्हें साथियों के साथ बातचीत करनी है। खेल मंत्री का बयान बताता है कि ज्यादातर मांगें पर सहमति बन गयी है। पहलवानों की ओर से जो पांच मांगें रखी गयी हैं, उनमें भारतीय कुश्ती महासंघ के स्टंक्टर और निष्पक्ष चुनाव करवाना, मौजूदा अध्यक्ष

जिस तरह के सूबत निल रहे हैं, उसी आधार पर जांच आगे बढ़ रही है और पुलिस की कार्रवाई भी उसी के अनुरूप होनी चाहिए। अगर किसी दबाव में उसे अलग करन उठा दिया जाता है, तो उसे तथ्यों की दीर्घी में अदालत में सही साधित करवाना चाहिए।

इन चार में कोई बड़ी दिवकर नहीं है। खबरें भी बताती हैं कि सरकार इन मांगों पर स्वीकार करने को कीरीब-कीरीब तैयार हो गयी है। मामला पांचवीं मांग को लेकर फंस रहा है, जिसे पहलवान अपनी मुख्य मांग के रूप में पेश करते आये हैं। वह है बजूधान शरण सिंह की गिरफ्तारी। जहाँ पहलवानों के लिए इस मांग पर दील देने का मतलब अपनी अब तक की लड़ाई को व्यर्थ कर देने जैसा है, वहाँ सरकार की एकआइआर दर्ज करने के बाद बजूधान चार्जरीसी पेश कर दी जाने के बाद अपने लोगों को देख रही है। जिस तरह के सूबत मिल रहे हैं, उसी आधार पर जांच आगे बढ़ रही है और पुलिस की कार्रवाई भी उसी के अनुरूप होनी चाहिए। अगर किसी दबाव में उससे अलग करन उठा दिया जाता है, तो उसे तथ्यों की रोशनी में अदालत में सही साधित करना मुश्किल हो जायेगा। शायद इसीलिए सरकार की तरफ से यह भरोसा दिलाया गया कि दिल्ली पुलिस जांच पूरी होने के बाद मजबूत चार्जरीसी पेश कर दी जाएगी लेकिन पहलवानों के लिए वह तब करना मुश्किल है कि मजबूत चार्जरी का ठीक-ठीक मतलब क्या निकलेगा। बरहाल, पहलवानों की शिकायतों और उनके विरोध प्रदर्शन में जुड़ा यह पूरा प्रकरण बहुत लंबा चिंच चुका है। यह और लंबा चला, तो देश की साथ को वाकई नुकसान पहुंच सकता है।

अभिमत आजाद सिपाही

नौ वर्ष पहले जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला था, तब भारत की धीमी आर्थिक विकास, उच्च बोरोजगारी और उच्च राजकोषीय घटे की स्थिति 1980 के दशक के संयुक्त साज्य अनेकिका जैसी ही थी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, सरकार ने ऐसे कई परिवर्तनकारी पहलों को लागू किया, जिन्होंने हमारे महान राष्ट्र को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाते हुए भारतीय समाज के सभी वर्गों के जीवन को प्रभावित किया है।

बदला हुआ भारत : मोदी सरकार के यादगार नौ वर्ष

किरण मजूमदार-शॉ

यह हमारे लिए इस बात को महसूस करने का समय है कि एक देश के तौर पर हम इनमें महान हैं कि खुद को छोटे सफरों तक सीमित नहीं कर सकते। हम वैसे नहीं हैं, जैसा कि कुछ लोग हमें मानते हैं। एक अपरिहार्य पतन के लिए अधिषंज्ञा में उस भाव्य में कर्तव्य विश्वास नहीं करता जिसका फल हम पर पड़ेगा ही, चाहे हम जो कुछ भी करें। मेरा भरोसा एक ऐसे भाव्य में है जिसका फल हम पर पड़ेगा, अगर हम कुछ भी नहीं करें। इसलिए, अपने नियंत्रण में उपलब्ध सभी रचनात्मक ऊर्जा को बटोरते हुए, अझे हम सब राष्ट्रीय नवीनीकरण के युग की शुरुआत करें। आगे हम अपने टूट संकल्प, अपने सामाजिक और आपनी ताकत को नये सिरे से सहेजें और आगे हम अपने विश्वास और अपनी आशा को नए सिरे से मजबूत करें। हमें बहादुरी भरे सपने देखने का पूरा अधिकार है।

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के उपरोक्त उद्धरण से यह बात प्रतिधिक्षिण होती है कि कैसे यह भारत के लिए बढ़े सपने देखने का समय है।

नौ वर्ष पहले जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला था, तब भारत की धीमी अर्थिक विकास, उच्च राजकोषीय घटे की रिपोर्ट-19 महामारी से निपटने के लिए एक देश के तौर पर नहीं रही थी, तो भारत नियंत्रण के नेतृत्व में, सरकार ने ऐसे कर्दे कई परिवर्तन करें। हमें बहादुरी भरे सपने देखने का पूरा अधिकार है।

नौ वर्ष पहले जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला था, तब भारत की धीमी अर्थिक विकास, उच्च राजकोषीय घटे की रिपोर्ट-19 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-20 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-21 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-22 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-23 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-24 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-25 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-26 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-27 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-28 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-29 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-30 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-31 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-32 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-33 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-34 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-35 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-36 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-37 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-38 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-39 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-40 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-41 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-42 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-43 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-44 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-45 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-46 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-47 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-48 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-49 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-50 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-51 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-52 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-53 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-54 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-55 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-56 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-57 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-58 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-59 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-60 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-61 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-62 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-63 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-64 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-65 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-66 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-67 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-68 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-69 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-70 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-71 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-72 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-73 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-74 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-75 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-76 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-77 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-78 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-79 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-80 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-81 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-82 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-83 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-84 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-85 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-86 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-87 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-88 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-89 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-90 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-91 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-92 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-93 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-94 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-95 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-96 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-97 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-98 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-99 महामारी से निपटने के प्रति धर्मांतरण की रिपोर्ट-100 महामारी से न

